have been taken to curb the evil of unaccounted incomes. In order to discourage under-valuation of property which has been an important avenue for the circulation of black money, Government have now got powers to acquire rroperties at prices that correspond to what is recorded in sale deeds. Legislation has also been enacted to discourage *benami* holding of property. The Direct Taxes Enquiry Committee has made a number of suggestions for unearthing black money and they are now under active consideration of Government.

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादन क्षमता

1653. **श्री ना० कृ० शेजवलकर :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
डा० भाई महावीर :
श्री पीताम्बर दास :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री ओम् प्रकाश त्यागी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में वस्तुवार वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) इसी प्रकार के गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे औद्योगिक उपक्रमों में जहां क्षमता बेकार पड़ी है, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

t [PRODUCTION CAPACITY OF PUBLIC SECTOR INDUSTRIES

1653. SHRI N. K. SHEJWALKAR : SHRI J. P. YADAV : DR. BHAI MAHAVIR : SHRI PITAMBER DAS : SriRI PREM MANOHAR : SHRI O. P. TYAGI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the percentage of actual production in relation to the total installed capacity, item-wise, in various public sector industries;

(b) the comparative position obtaining in the corresponding private sector industries; and

(c) the efforts being made to increase production where there is idle capacity in public sector industrial undertakings?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अनुबन्ध I देखिये परिशिष्ट LXXXII अनुपत्र संख्या 80] में मुख्य सरकारी उद्योगों में क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति बतायी गयी है ।

(ख) अनुबन्ध II [देखिए परिशिष्ट LXXXII अनुपत्र संख्या 81] में निजी क्षेत्र में वस्तुओं के अनुसार, क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में बताया गया है । सरकारी क्षेत्र में बनायी जाने वाली बहुत सी वस्तुएं निजी क्षेत्र में नहीं बनती इसलिए हर मामले में तुलना नहीं की जा सकती है ।

(ग) सरकारी उद्यमों में क्षमता के उपयोग में और वृद्धि करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं ।

(1) उत्पादन संबंधी बेहतर आयोजन करना और नियंत्रण तकनीक अपनाना ।

(2) जहां आवश्यक हो, दुर्लभ कच्चे माल और हिस्सों का आयात करना ।

(3) संयंत्र और उपकरणों का बेहतर अनरक्षण ।

(4) उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के द्वारा उच्च श्रम उत्पादकता करना ।

(5) औद्योगिक संबंध सुधारना और

t[ ] English translation.

(6) जहां कम निकासी के कारण उत्पादन रुक गया हो वहां मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन में विविधता लाना और निर्यात प्रोत्साहन संबंधी उपाय करना ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) Annexure I [See Appendix LXXXII, Annexure No. 80] gives the position regarding capacity utilisation in the major public enterprises.

(b) Annexure II *[See* Appendix LXXXII, Annexure No. 81] gives the capacity utilisation, commodity-wise, in the private sector. Many of the items produced in the public sector are not produced in the private sector to allow a camparison to be made in all cases.

(c) The important steps taken to improve the capacity utilisation in public enterprises are:—

(i) adoption of better production planning and control techniques;

(ii) import of critical raw materials and components, where necessary;

(iii) better maintenance of plant and equipment;

(iv) higher labour productivity by production incentive schemes, training programmes, etc.;

(v) improved industrial relations; and

(vi) diversification and export promotion measures to improve demand, where production has been inhibited by poor offtake.]

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों का धरना

1654. श्री सूरज प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 सितम्बर 1972 को पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों ने धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए है ?

TT'DHARNA* BY EMPLOYEES OF STATE BANK OF INDIA, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI

1654. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Parliament Street, New Delhi Branch of the State Bank of India staged a "Dharna" on the 14th September, 1972;

(b) if so, the details about their demand; and

(c) the steps taken to meet their demands?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) नव निर्मित दिल्ली सर्कल स्टेट बैंक कर्मचारी संघ , नई दिल्ली से संबंधित कर्मचारियों के एक वर्ग ने जो कि बैंक के पंचाट स्टाफ का एक गैर मान्यता प्राप्त संघ है, 14 सितम्बर, 1972 को कार्यालय के समय के पश्चात्, प्रदर्शन किया था ।

(ख) उन की मांगों का संबंध, मजदूरों के विरुद्ध कुछ बर्खास्तगी के आदेश वापिस लेने , अस्थाई कर्मचारियों को खपाने, प्रशिक्षण अवधि के दौरान समयोपरि भत्ते की अदायगी करने , पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित बैंक की इमारत की देखभाल के लिए ठेका प्रणाली की समाप्ति करने , गैर मान्यता प्राप्त संघ की सहायता के साथ स्थानीय क्रियान्वयन समिति का निर्माण करने , प्रति-पूर्ति योग्य रकम की सीमा के बिना चिकित्सा संबंधी सहायता करना आदि से था ।